Haryana Vidhan Sabha

Debates

21st March, 1967

Vol. I-No. 2

Contents

Tuesday, the 21st March, 1967

	Pages
Starred Questions and Answers	1-9
Call Attention Notice	9
Governor's Address laid on the table	9-23
Announcement by Secretary	24
Obituary references	24-27
Presentation of the Financial Statement for the period from 1st November, 1966 to 31st March, 1967	27-30

Errata

To

HARYANA VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 2.

DATED 21ST MARCH, 1967.

Read	For	Page	Line
रवायत	खायत	(2)1	28
Krishan	Krshan	(2)3	31
हुआ	हआ	(2)6	24
देश	`श	(2)7	14
सहुलियत	सहूलत	(2)8	7
जो	जा	(2)8	9
व्रतों	त्रतों	(2)10	28
पुनर्गठन	पुनगठन	(2)12	17
गेहूं	`हूं	(2)13	10
सप्लाई	सरलाई	(2)13	15
सिंचाई	सिंजाई	(2)13	21

इसके	इरके	(2)13	35
Add में before	सहायता	(2)14	15
मरम्मत	मरम्नत	(2)14	31
स्टेशनों	स्ेशनों	(2)16	33
जिम्मेदारी	जिम्मेदा ी	(2)16	33
गांवो	गावो	(2)17	18
विमान	विभाग	(2)18	12
और	ओर	(2)18	15
गलाइडर	गुलाइडर	(2)18	18
क्षेत्रों	क्षेवों	(2)19	14
लाख	लख	(2)20	17
पूंजी	पूजी	(2)20	26
सैटों	सटों	(2)23	30
विधान	बिधान	(2)27	27
कार्यों	कार्यी	(2)29	18

ਹੈਂ	ਹੁੈਂ	(2)29	20

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, the 21st March, 1967

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Chandigarh-1, at 11 A.M. of the Clock. Mr. Deputy SPEAKER (Ch. Manphul Singh) in the Chair.

(STARRED QUESTIONS AND ANSWERS)

Future of Chandigarh and Bhakra

1. Sh. Daya Krishan: Will the Chief Minister be pleased to state whether the Central Government has consulted the Chief Minister with regard to the future of Chandigarh and of Bhakra; if so whether any assurance has been given by the Chief Minister to the Central Government?

Sh. Bhagwat Dayal Sharma: 1st Part No.

2nd Part Does not arise.

Sh. Daya Krishan: Will the Hon. Chief Minister be pleased to state as to what is the present position with regard to Chandigarh and Bhakra?

Chief Minister: As it was.

Sh. Daya Krishan: What it was, Sir?

Chief Minister: It is known to everybody.

(At this stage two/three hon. Members rose to put a supplementary question)

Mr. Deputy Speaker: Sh. Mangal Sein.

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे.....,

श्री दया कृष्णः डिप्टी स्पीकर साहिब, क्वैस्चन मैंने पुट किया है, इसलिए पहले सप्लीमेंटरी करने का मेरा हक है।

श्री उपाध्यक्षः आप डा0 मंगल सैन जी के बाद सप्लीमैंटरी पुट कर लें, अब मैं उनको बुला चुका हूं।

श्रीमति लेखवती जैनः डिप्टी स्पीकर साहिब, यह एक खायत है कि हाउस में जो मैम्बर सवाल पुट करता है, पहले उसका हक है। उसके बाद दूसरे मैम्बर को सप्लीमैंटरी पुट करने का हक है।

श्री उपाध्यक्षः डा0 मंगल सैन को अब मैं काल कर चुका हूं।

Smt. Lekhwati Jain: It is against the rules and the conventions of the House.

Sh. Daya Krishan: On a point of order, Sir.

Mr. Deputy Speaker: Order Please.

Smt. Lekhwati Jain: If there is a point of order, the Chair should hear it first.

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले दिनों जब सन्त फतह सिंह जी ने मरण–व्रत रखा हुआ था कि चंडीगढ और भाखड़ा को पंजाब में मिलाया जाये, तो इस सम्बन्ध में भारत

की प्रधान मंत्री श्रीमति इंद्रा गांधी से क्या कोई आपका वातलिाप हुआ था ?

मुख्य मंत्रीः जहां तक वातलिाप का ताल्लुक है वह तो अक्सर होता ही रहती है चंड़ीगढ और भाखड़ा के बारे में हरियाणा सरकार का जो स्टैंड रहा है, वह वही रहा हैक जो पहले था और उसकी हम पुथ्ष्ट करते रहे हैं, आज हमारा स्टैंड यह है कि चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है क्योंकि बाउंडरी कमीशन ने इसको हरियाणा को दिया है, लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूनियन टैरिटरी घोषित करके अपने अधीन रख लिया हुआ है। जब सन्त फतह सिंह और रिपब्लिकन पार्टी ने दावा किया कि चंड़ीगढ पंजाब में मिलना चाहिए तो हमने जोरदार शब्दों में कहा और दावा किया कि चंडीगढ हरियाणा का है और हरियाणा को मिलना चाहिए।

जहां तक भाखडा का ताल्लुक है, भाखडा के बारे में हमारा वही स्टैंड है जो पहले था। किन्तु इसका उपयोग हरियाणा के लिए है, यह हरियाणा के लिए बना है, इसलिए इस पर हरियाणा का ही हक है। चूंकि भाखड़ा हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र है इसलिए इस पर हरियाणा वालों का ही अधिकार है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि भाखड़ा हिन्दी भाषा–भाषी क्षेत्र है और चंडीगढ के बारे में भी बड़े जोरदार शब्दों में दावा किया है। क्या उनके जोरदार शब्दों में कहने के कोई परिणाम निकले हैं ?

मुख्य मंत्रीः यह प्रश्न बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री मंगल सैनः आवश्यक है, अनावश्यक कैसे ?

मुख्य मंत्रीः परिणाम यह निकला कि जितने भी विवादास्पद मामले थे वह सारे के सारे पंच फैसले के लिए दे दिए गए हैं।

श्री मंगल सैनः मुख्य मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि जितने स्प्युटिड इशू थे वह सब पंच फैसले के सुपुर्द कर दिये गये हैं, तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि वह पंच कौन है, टर्म्ज आफ रैफैस क्या है और उनका निर्णय कब तक होने वाला है ?

मुख्य मंत्रीः इसका निर्णय करना हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के हाथ में है। जहां तक टर्म्ज आफ रैफैंस का ताल्लुक है उसके लिए कोई निश्चित अवधि निश्चित नहीं की गई।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह अवधि अनंत काल तक जारी रहेगी या उसकी तय करने जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्रीः यह अधिकतर पंच निर्णय पर निर्भर करता है कि कब इसकी तारीख निश्चित करें। चूंकि अभी अभी चुनाव समाप्त हुए हैं और देश के समक्ष और बड़ी समस्याएं रही हैं, इसलिए इस विषय को नहीं लिया गया।

Mr. Deputy Speaker: Sh. Daya Krishan may please put his supplementary question.

Sh. Daya Krishan: No supplementary now.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या चंडीगढ सैन्ट्रल गवर्नमैंट का है ? इसके अतिरिक्त क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ हरियाणा का रहेगा या यह मामला डिस्प्यूट में ही रहेगा ?

मुख्य मंत्री: जिस समय बाउडंरी कमीशन ने चंडीगढ के बारे में अपना फैसला दिया था तो उस फैसले में चंडीगढ को बहुमत से हरियाणा में दिया गया था। किन्तु भयानक परिस्थितियों से बचने के लिए यह सैंन्ट्रल गवर्नमैंट ने अपने अधीन रख लिया अर्थात् इसको यूनियन टैरिटरी बनाकर अपने अधीन रख लिया किन्तु हक तो हमारा था और कमिशन का निर्णय भी हमारे हक में है, लेकिन देश में अशान्ति पैदा होने की जो सम्भावनाएं थीं उनको दूर करने के लिए सैंन्ट्रल गवर्नमैंट ने चंडीगढ को अपने अधीन रखाा और इस फैसले को हम सभी ने स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब यह झगड़ा दुबारा पैदा हुआ तेा जिसका वाजिब हक बनता है वह फिर उसका दावेदार बन सकता है। कमीशन का फैसला हरियाणा के पक्ष में है इसलिए चंडीगढ के दावेदार हम हैं।

Mr. Deputy Speaker Starred Question No. 3 (Postponed)

Sh. Daya Krishan: What about my Starred Question No. 3 ?

Mr. Deputy Speaker: Government have asked for extension to reply this question.

Sh. Daya Krishan: By what date, Sir ?

Mr. Deputy Speaker: No date has been specified.

Sh. Daya Krishan: Will you kindly fix some date for getting me a reply to this question.

Chief Minister: The hon. Member will get the reply soon.

Supply of Food – Grains and Atta

2. Sh. Daya Krishan: Will the Minister for Health be pleased to state the arrangements which the Government has made to provide sufficient foodgrains/Atta to the public for the future in view of the failure of the crops in the State. ?

Sh. Dev Raj Anand: A statement containing the required information is placed on the Table of the House.

Statement Regarding Supply of Food Grain and Atta

Regulated distribution of wheat/atta, rice and bajra has been taken up all over the State through a net work of about 1500 fair price shops. The State Government has sufficient stocks of wheat/atta to meet the requirement of consumers till the arrival of new Rabi crop in the market. About 15000 tonnes of rice are at present held in the Provincial Reserve for distribution through fair price shops throughout the State and these stocks will be sufficient to last till the arrival of the new rice crop in October, 1967.

The State Government have decided to procure one lakh tonnes of country wheat and 25000 tonnes of rice during the ensuing season. The stocks of country whet will be supplemented by supplies of imported wheat from the Government of India which are at present allotted by them at

the rate of 10000 tonnes per month. The building up of buffer stocks of wheat and rice by State Government which will be released to consumers as and when required through fair price shops, will help in maintaining the prices of food-grains in the State at reasonable level.

श्री दया कृष्ण: क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि देहातों में अनाज की जो तकसीम इस समय हो रही है वह नातसल्लीबख्श है ?

मंत्री: अनाज का वितरण 50 फीसदी पापुलेशन को इस समय किया जा रहा है।

श्री दया कृष्ण: मेरा मतलब यह है कि जिस तरह अनाज की तकसीम हुई है यह हो रहीं वह ठीक नहीं है। जिन लोगों को तकसीम होना चाहिए था उनको अनाज नहीं मिल रहा। गरीब लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, क्या वजीर साहिब के नोटिस में यह बात है ?

मंत्री: जो लेबर है, गरीब आदमी हैं उनको पहले अनाज दिया जा रहा है और बाकियों को बाद में।

श्री दया कृष्ण: क्या माननीय मंत्री महोदय कृप्या बताएंगे कि जिन गरीब आदमियों में या दूसरे ऐसे आदमियों में जिन्हें अनाज दिया जा रहा है, जमींदार भी शामिल हैं अर्थात् गरीब आदमियों की परिभाषा में जमींदार भी शामिल हैं।

मंत्रीः देहातों में जो गरीब आदमी होते हैं, उनमें नौकरी पेशा लोग नहीं रहते, दूसरे लोग होते हैं।

श्री श्री कृष्णः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गरीब की कैटेगरी में किस–किस को लिया गया हैं ?

मंत्रीः हरिजन्ज, लेबरर्ज एण्ड लैंडलैस लेबरर्ज।

श्री श्री कृष्णः क्या मंत्री महोदय कृप्या बतायेंगे कि क्या जो छोटे छोटे जमींदार देहातों में रहते हैं, उनको भी गरीब की कैटेगरी में शामिल किया गया है ?

मंत्रीः उनको भी शामिल किया जाएगा।

श्री श्री कृष्णः यदि 50 फीसदी पापुलेशन को इस वक्त देहातों में अनाज तकसीम किया जा रहा है तेा मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बाकी लोगों को कब तक अनाज तकसीम किया जाएगा ?

Minister: As soon as the 'Gazai' position is better.

श्री मुख्य मंत्रीः डिप्टी स्पीकर साहिब, आज मैं हरियाणा के एक बहुत ही मायानाज सपूत की यादगार में श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा।

श्री उपाध्यक्षः चीफ मिनिस्टर साहिब, अभी सप्लीमैंटरी वैवस्चन बाकी हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब शायद पंडित जी को जल्दी जाना है।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, उनको ध्यान नहीं रहा।

श्री मंगल सैनः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब कि राज्य भर में अनाज की किल्लत के कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या अनाज को कंज्यूमर्ज तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई प्रबन्ध किया हैं ?

Minister: Regulated distribution of wheat/Atta, rice and bajra has been taken up all over the State through a network of about 1500 fair price shops. The State Government has sufficient stocks of wheat/atta to meet the requirements of consumers till the arrival of new Rabi crop in the market. About 15000 tonnes of rice are at Present held in the Provincial Reserve for distribution through fair price shops throughout the State and these stocks will be sufficient to last till the arrival of the new rice crop in October, 1967.

The State Government have decided to procure one lakh tonnes of country wheat and 25000 tonnes of rice during the ensuing season. The stocks of country wheat will be supplemented by supplies of imported wheat from the Government of India which are at present allotted by them at the rate of 10000 tonnes per month. The building up of buffer stocks of wheat and rice by State Government, which will be released to consumers as and when required through fair price shops, will held in maintaining the prices of foodgrains in the State at reasonable level.

मेजर अमीर सिंहः क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जिला महेन्द्रगढ के फैमिन स्ट्रिकन एरिया को जो सबसिडाइज्ड फूडग्रेन्ज देने से महरूम कर दिया गया है इसकी क्या वजह है ?

मंत्रीः मैनें कल ही करनाल में डी.एफ.सीज की कांफ्रैस में हिदायत की है िकवह मौका पर जा कर देखें और जहां किल्लत है उसे दूर करने की कोशिश करें और सप्लाई का इंतजाम करें।

मेजर अमीर सिंहः क्या यह अनाज मजदूरों को ही दिया जाएगा या गरीब किसानों जिनकी फसल मारी गई हैऔर खाने को अनाज नहीं हुआ है, को भी दिया जाएगा ?

मंत्रीः मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि गरीब किसानों, जिनके पास अनाज नहीं, को भी दिया जाएगा।

मेजर अमीर सिंहः क्या यह बात वजीर साहिब के इल्म में है कि महेन्द्रगढ में शादियों के लिए भी चावल देना बन्द कर दिया गया है ?

मंत्रीः ऐसा गवर्नमैंट आफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक ही किया गया है।

मेजर अमीर सिंहः क्या यह वजीर साहिब के इल्म मे है कि जिला महेन्द्रगढ में 50 फीसदी गांव ऐसे हैं जहां तीन चार महीने से शूगर नहीं मिली है ?

मंत्रीः अभी तक यह बात नोटिस में नहीं लाई गई थी अब आपने बताया है तो I will look into it.

श्रीमति लेखवती जैनः वजीर साहिब ने बताया है कि देहात में 50 फीसदी को इस वक्त राशन दे रहे हैं लेकिन क्या उनके इल्लम में हैं कि 50 फीसदी से ज्यादा ही गांव में रहते हैं जिसका मतलब है कि सारे के सारे हरिजनों को भी राशन नहीं मिलता है बाकी गरीब लोगों की तो बात ही छोड़ो। गांव में कुछ हरिजनों को अगर राशन मिल जाए और बाकी को कुछ न मिले तो क्या यह डिसकिमीनेशन नहीं है ? क्या इस डिसकिमीनेशन को दूर करेंगे ? कम से मकस जितने गांव में हरिजन हैं उनकी तो सबको राशन मिलना चाहिए।

मंत्रीः जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गिजाई सूरते हाल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है हम गवर्ननमैंट आफ इंडिया से टेक–अप कर रहे हैं और हालात बेहतर होते ही तमाम दिक्कत दूर की जाएगी।

श्रीमति लेखवती जैनः मैं पूछना चाहती हूं कि हम जो गरीबों की तरफ से चुनकर आए हैं उन्हें जाकर क्या जवाब दें चन्द हरिजनों को तो अनाज मिल जाता है और चन्द हरिजनों को नही मिलता है। जो रह जाते हैं वह कहते हैं कि उनका क्या कसूर है जेा उन्हें अनाज नहीं मिलता। सरकार को इस बारे में

सही पालिसी बनानी चाहिए और यहां बताना चाहिए कि वह इस बारे में क्या कर रही है जिससे यह डिसकिमीनेशन दूर हो सके।

मंत्रीः बहन जी, मैंने अर्ज किया है कि जो गिजाई हालत आज देश में है .....

Smt. Lekhwati Jain: In the House, he should address the Chair and not the member. This has been the convention. Of course, he can address me as 'Bahen Ji' outside the House.

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या इस हाउस में दो मैम्बर जिनका आपस में जाति या पोलिटिकल झगड़ा हो हाउस में सीधे तौर पर इसतरह बातें कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्षः कोई पर्सनल बात नहीं हो सकती।

श्रीमति लेखवती जैनः हरिजनों के विषय में मैं यह कहना चाहती हूं कि देहात में उन सबको राशन मिलना चाहिए।

मंत्रीः मैंने अर्ज किया है कि मौजूदा गिजाई सूरते हाल को देखते हुए तो 50 फीसदी को देने का ही फैसला किया गया है बाकी पोजीशन बेहतर होते ही हम कोशिश करेंगे कि देहात में रहने वाले तमाम लोगों को अनाज सप्लाई किया जाए।

श्रीमति लेखवती जैनः मैं वजीर साहिब से पूछना चाहती हूं कि एक तरफ तो देहांत में सभी हरिजनों को राशन नहींदे सके हैं कुछ को मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा और उसके

लिए गवर्नमैंट ने कोई पालिसी बनाई दूसरी तरफ उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जिन के पास पांच एकड़ जमीन है उनको भी राशन मिलेगा, यह कैसे होगा इस तरफ भी क्या इस गवर्नमैंट ने ध्यान दिया है ?

मंत्रीः मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि गिजाई सूरते हाल को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि गर्वनमैंट आफ इंडिया से ज्यादा से ज्यादा अनाज लिया जाए। जिस वक्त भी अनाज की पोजीशन स्टेट में बेहतर होती है, देहात में रहने वाले तमाम भाईयों की तरह से राशन देने की पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह कि शहरों में दिया जाता है। इस मामले को हम गवर्नमैंट आफ इंडिया के साथ बड़ी मजबूती से टेक अप कर रहे है। अभी 21 हजार टन अनाज हमने उनसे 31 मार्च तक लेना है और हम कोशिश करेंगे कि वह हमें जल्दी से जल्दी मुहैया करें ताकि हम तमाम स्टेट के लोगों को यह सहूलत मुहैया कर सकें।

श्रीमति लेखवती जैनः डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहती हूं कि देहात में जा सारे हरिजनों को और पांच एकड़ तक जमीन वालों को राशन नहीं मिलता है और वहां सबको अनाज की तंगी है तो कभी उन्होंने सोचा है कि शहरों मे सब लोगों को जिनमें रूप्ए पैसे वाले लोग, बड़े बड़े कारखानों के मालिक और दूसरे अमीर लोग शामिल हैं उन सब को राशन मिलता है हालांकि वह महंगे भाव पर खरीदने की शक्ति रखते हैं परन्तु गांव में सारे गरीब हरिजनों और पांच

एकड़ तक के गरीब किसानों को जिनकी खेती नही हुई है बारिश न होने की वजह से उनको नहीं दिया जाता शहरों में खुला अनाज बिकता है, अमीर आदमी वहां खुले बाजार में खरीद सकते हैं। क्या वह इस चीज पर विचार करेंगे और .....

Mr. Deputy Speaker: Please do not make a speech, put your supplementary only.

श्रीमति लेखवती जैनः क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार की पालिसी क्या है जबकि गांव के अन्दर पांच एकड़ जमीन रखने वालों को आटा नहीं दिया जाता मगर शहर के अन्दर कारखानों के मालिकों को काफी मात्रा में सब चीजें मिल जाती है ?

मंत्रीः डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर चुका हूं, मगर उनके ख्याल में नहीं आया। मैंने इन्हें बताया है कि मैंने हिदायत जारी की है कि पांच एकड़ से कम जमीन वाले देहात में रहने वाले जमींदार जो हैं उनको भी राशन दिया जाए और अब उनको भी राशन मिलेगा।

श्री भगवान देव प्रभाकरः क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि फरवरी के महीने में लेबर क्लास के राशन में जो पर हैड चार किलो की बढौती की गई थी वह अब मार्च में क्यों बन्द की दी गई है ?

मंत्रीः डिप्टी स्पीकर साहिब, हमें पंजाब में कुछ अनाज मिला था इस लिए हमने राशन की मात्राा बढ़ा दी थी। अब क्योंकि कुछ कमी है इसलिए मात्रा घटा दी गई है लेकिन अब भी ज्यों ही पोजीशन बेहतर होगी राशन का कोटा बढ़ा दिया जाएगा।

श्री भगवान देव प्रभाकरः क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताएंगे कि हिसार जिला को चीनी देने के लिए सरकार क्या स्टैप उठा रही है क्योंकि वह वहां से अब तक गायब थी ?

Minister: Sir, this supplementary does not arise out of the main question.

श्री मंगल सैनः क्या हमारे खुराक के वजीर साहिब फरमायेंगे कि चार किलो राशन बढ़ने का कारण पंजाब से अनाज आ जाने के सिवाय यह भी था कि उस समय आपको गरीब मजदूरों से वोट लेने थे और अब क्योंकि काम निकल गया है इसलिए यह कम कर दिया गया है ?

मंत्रीः मेरे दोस्त को यह गलत फहमी है कि हमें पजाब से अनाज मिला था जिस वास्ते हमने राशन बढ़ा दिया था। अब भी हम कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त भी मुहैया करेंगे हम फिर राशन बढ़ा देंगे।

कंवर रामपाल सिंहः क्या मंत्री जी बताएंगे कि देहात में क्या और अधिक राशन की दुकानें खोली जाएंगी ?

मंत्री: जहां जरूरत समझी जाएगी वहां खोल दी जाएगी।

Mr. Deputy Speaker: Now question hour is over and the next item on the agenda is a Call Attention Notice.

CALL ATTENTION NOTICE

Mr. Deputy Speaker: I have received a Call Attention Notice from Pandit Bhagwan Dev Prabhakar regarding scarcity of drinking water at Bhiwani Town etc. I postpone my decision about its admission. I shall think over it and give my decision about its admission tomorrow.

GOVERNOR'S ADDRESS

(COPY LAID ON THE TABLE)

Mr. Deputy Speaker: In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. I have to report that the Governor was pleased to Address the Haryana Legislative Assembly on the 20th March, 1967 under article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

Governor's Address

साथियों !

चुनावों में सफलता पर आपको बधाई देते हुए हरियाणा की नई विधान सभा मे आपका स्वागत करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है।

डाक्टर गोजी चन्द भार्गव के दु:खद निधन से राज्य को बहुत हानि हुई हैं। डाक्टर भार्गव हरियाणा के ऐसे महान सपूत नेता थे जिन्होंने स्वतन्त्रता–संग्राम में भाग लेकर निष्काम सेवा और त्यागमय जीवन का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने राजनैतिक जीवन में बड़ा प्रमुख और सक्रिय भाग लिया तथा समाज–सेवा एवं खादी के काम में ख्याति प्राप्त की। जीवन के अन्तिम क्षणों तक वे इन्हीं कार्यों में जुटे रहे। इस महान पुरूष के निधन से न केवल राज्य को बल्कि सारे देश को ही बहुत क्षति पहुंची हैं।

चौथे आम चुनाव के बाद बनाई गई नई विधान सभा का यह पहला अधिवेशन है। हमस ब के लिए यह गौरव और बधाई का विषय है कि देश को आजादी मिलने के बाद चौथी बार लगभग 25 करोड़ मतदाताओं ने निर्भीक एवं निष्पक्ष ढ़ग से मतदान किया है। हाल के इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय गणतन्त्र–सजीव है और सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना का क्षितिज उमर रहा है तथा मतदाता की इच्छा ही सर्वोच्च है। मतदाताओं का विश्वास प्रापप्त करने वाले आप सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं तथा आशा रखता हूं कि आप अपनी शक्ति आने चुनने वालों अर्थात् हरियाणा के लोगों की रचनात्मक ढंग से सेवा करने में जुटा देंगे तथा

हरियाणा को प्रगतिशील वं समृद्ध राज्य बनाने में पूरा सहयोग दैंगे। मुझे यह भी आशा है कि आपइस सदन के सदस्य रहते हुए इसकी सारी कारवाई बड़े गौरव, शिष्टता और सम्मान के साथ चलाएंगे और जिन लोगों ने आपको चुनकर राज्य को सेवा का मौका दिया है, उनकी आशाओं को पूरा करेंगे।

हरियाणा राज्य को बने अभी केवल पांच ही महीने हुए है, परन्तु सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रही है कि राज्य में शान्ति की स्थापना कर के और आर्थिक तथ विकास सम्बन्धी योजनाओं को तेजी के साथ पूरा करके लोगौं की उन्नति और खुशहाली को बढ़ावा दिया जाए। जहां तक राज्य के सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध है, यह खुशी की बात है कि कानून और व्यवस्था कि स्थिति सोर वर्ष के दौरान साधारण रही। चुनाव से पहले सारे देश में विद्यार्थियों में बेचैनी फैली हुई थी, जिसके कारण हड़ताले और हिंसक कारवाइयां हुई। हरियाणा के विद्यार्थियों को इस बात का श्रेय है कि उन्होनें बाहर से उकसाहट मिलने पर भी सराहनीय और संयमपूर्ण व्यवहार का परिचय दिया। राजनीतिक उद्देश्य के लिए रखे गए तंत्रों और जवाबी तंत्रों के कारण हरियाणा के भागों में और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थिति बड़ी चिन्ताजनक और कठिन थी परन्तु प्रशासकीय अमले द्वारा बरती गई सावधानी और उठाए गए ठोस उपायों से राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनी रहीं। यह बड़े संतोष की बात है कि हरियाणा के कुछ इक्का–दुक्का घटनाओं को छोड़कर चुनाव का सारा काम

ठीक ढंग से पूरा हुआ सिविल तथा पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कठिन जिम्मेदारी को निभाने के लिए मौके पर पूरा उतरी और वह इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने पर बधाई का पात्र है। अपराधों की संख्या भी चिन्ताजनक नहीं है। चोर बाजारी, जमाखोरी तथा चोरी छिपे व्यापार करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अनाज के चोरी छिपे व्यापार की रोकथाम के लिए मुख्य सड़कों तथा दूसरे राज्यों के साथ मिलने वाली सीमाओं पर चौकियां बिठा गई हैं और अब स्थिति काबू में है।

चालू साल के दौरान सरकारी कर्मचारियों में कुछ अशान्ति थी। बढ़ती कीमतों के कारण तनखाह लेने वाले व्यक्तियों, विशेषकर थोड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई चाहती है और इसलिए उसने पहली जनवरी, 1967 से एक हजार रूप्ए तक वेतन पाने वाले अपने कर्मचारियों का मासिक महंगाई भत्ता 10 रूपए से लेकर 20 रूप्ए तक बढ़ा दिया। महंगाई भत्ते के बढ़ाने से लगभग 96000 कर्मचारियों को लाभ हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को और अधिक सहायता देने के वास्ते किसी लाभ या हानि के बिना सस्ती दुकानें खोलने के लिए उपाय किए गए हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी की जा सकें। सरकार इन दुकानों के खोलने का सारा प्रारंभिक खर्च उठाएगी। सरकार ने इस बात की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में मान लिया है कि कर्मचारियों

सम्बन्धी नीतियां बनाते समय उनहे इसमें अधिक से अधिक भाग लेने का मौका दिया जाए। सरकार तथा उसके कर्मचारियों के बीच भारत सरकार की तरह ही आपसी सलाह मशविरे तथा बीच बचाव कराने की व्यवस्था के लिए काम शुरू हो चुका है। कई सेवाओं के अधिकारियों ने भी मांग की है कि दूसरे कारणों के इलावा कीमतों में हो रही बहुत अधिक बढ़ती को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान (पे स्केल) बढ़ाए जाने चाहिए। इसके बारे में सरकार ने यह फैसला किया है कि उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए जो सम्पूर्ण सेवाओं के वेतनमानों की व्योरेवार जांच करें। इससे सेवाओं के मामले पर अलग अलग विचार करने की बजाय इन पर व्यापक तथा समूचे तौर पर चिार हो सकेगा। यह बाता उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य के कर्मचारियों ने हड़तालों तथा अन्य गैर–कानूनी कार्यों में हिस्सा न लेकर और प्रशासन तथा जनता के हितों को दूसरी छोटी बातों से ऊपर रखकर जिस महान जिम्मेदारी की उच्च भावना का परिचय दिया है उसके लिए वे प्रशंसा के हकदार हैं।

सरकार की बड़ी इच्छा है कि ऐसे उपाय किए जाए, जिनसे करों के निर्धारण तथा वसूली के लिए अपनाई जाने वाली विवरणियों आदि को कम कर दिया जाए और यदि हो सके तो ऐसे पेचीदा तरीकों को समाप्त किया जाए, जिनसे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों की करों संबंधी सलाहकार समिति बनाने का

निर्णय किया गया हैं जोकि विभिन्न करों के प्रबन्ध में सुधार के लिए सुझाव दें। यह निर्णय किया गया है कि एक बिक्री कर न्यायाधिकरयण (ट्रिब्यूनल) कायम किया जाए, जिसका विभागीय एजेंसी से सम्बन्ध न हो और जो कर–निर्धारण के विरूद्ध अपीलों आदि को जल्दी से निपटाए। उनके व्यापार की बहाल करने के एिल कच्ची उन पर लगने वाले कर को 6 प्रतिशत से घटा कर 2 यप्रतिशत कर दिया गया है। कुरूक्षेत्र तथा पिहोवा की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निश्चय किया गया है कि अगले बित वर्ष के शुरू से वहां पर नशाबन्दी लागू कर दी जाए।

हरियाणा के नए राज्य को बड़ी गंभीर खाद्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गई है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि अप्रैल, 1966 के महीनें में हरियाणा की मुख्य फसलों चनों और गेहूं के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था ताकि उसमे उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में से गेहूं और चने के भण्डार बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में ले जाए गए और यहां के भण्डार बहुत कम हो गए। इसके इलावा समूचे तौर पर देश में अनाज की पैदावार काफी कम हो गई। वर्ष 1967–65 में पैदावार काअनुमान 8.70 करोड़ टन था। वर्ष 1965–66 में यह पैदावार वर्षा न होन के कारण कम से कम स्तर तक पहुंच कर 7.20 करोड़ टन रह गई।

पुनगठन के समय राज्य के अंदर केवल 27,000 टन गेहूं था। इन भण्डारों को बढ़ाने के एिल बाहर से मगवाए गए गेहूं का कोटा बढ़ाने का मामला केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया गया और पुनर्गठन से अब तक बाहर से मंगवाया गया लगभग 49,000 टन गेहूं राज्य के लिए नियत हो सका है। गेहूं भण्डारों को बढ़ाने के लिए लगभग 45,000 टन बाजरा भी प्राप्त किया गया।

राज्य के लोगों को उचित कीमतों पर गेहूं, बाजरा और चावल देने के लिए राज्य में सस्ते अनाज की लगभग 1500 दुकानें खोली गई हैं। हरिजनों, औद्योगिक कामगरों और भूमि–रहित मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष डिपो खोले गए है। जिला अधिकारियों को अधिकार दियागया कि वे जहां कहीं भी जरूरत हो, सस्ते अनाज की और दुकानें खोल दें। देसी गेहूं के लिए 105 रूपए प्रति क्विंटल बाजार भाव के मुकाबले सस्ते अनाज की सरकारी दुकानों पर साधारण किस्म का गेहूं 77 रूपए प्रति क्विंटल और अच्छी किस्म का गेहूं 81 रूपए प्रति क्विंटल (बिक्री कर छोड़ कर) के दर से बेचा जाता है। इसी प्रकार डिपुओं पर बाजरा 71 रूपए प्रति क्विंटल बेचा जात है जब कि मंडी में इस का भाव 86 रूपए प्रति क्विंटल है।

सरकार ने अनिवार्य रूप से चावल प्राप्त किया है। चावल की कुल पैदावार का 80 प्रतिशत सरकार खरीद लेती है और बाकी 20 प्रतिशत खुली बिक्री के लिए छोड़ दिया जाता है। इस योजना के अधीन अब तक 850000 टन चावल खरीदा जा

चुका है। जिसमें स`अब तक 34000 टन राज्य के सुरक्षित भंडार के लिए और 51000 टन भारत सरकार के लिए खरीदा गया है।

देर स`चल रहे सूखे के कारण इस वर्ष रबी की फसल की बहूत अधिक हानि हुई है। बारानी फसलें तो लगभग 50 प्रतिशत खराब हो गई हैं परन्तु सौभाग्य से चाही फसलों को अधिक हानि नहीं हुई। इसलिए पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष समूची अनुमानित पैदावार केवल 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की आशा नहीं है। इस समय सरकार अगली रबी फसल के समय अनाज की उगाही और उसको बांटने के बारे में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार कर रही है। अभी इस बारे में कुछ पता नहीं कि भारत सरकार पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश को भी खाद्य क्षेत्र मे शामिल रखेगी या नहीं। परन्तु फिर भी उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र से निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार को मनाने के जोरदार प्रयत्न किए जाएंगे। ताकि पंजाब और हरियाणा के गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र अपना फालतू गेहूं सरकारी स्तर पर कमी वाले राज्यों को भेज सकें और उत्पादक को भी ऐसा आकर्षक मूल्य दिलाया जा सके जा कि उपभोक्ता के एिल भी वाजिब हो । सरकार हर हालत में वर्ष के तंगी वाल महीनों के दौरान जरूरत को पूरा करने और अनाज की बेहद बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के एिल काफी सुरक्षित भंडार जमा करेगी।

पत्थरी कोयले, सामान्य कोयले, ईटों और मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। बढ़ती हुई मांग को

पूरा करने के एिल सीमेंट का कोटा बढ़वाने का यत्न किया जा रहा है।

भूमि के नीचे क`जल भंडारों को ढूंढ निकालने और उनसे लाभ उठाने की जरूरत पर जोर देने का महत्व स्पष्ट ही है और इस संबंध में छोटी सिंचाई योजनाओं का सब से अधिक महत्व है। चौथी योजना की बाकी अवधि के दौरान छोटी सिंजाई योजनाओं के लिए 8.8 करोड़ रूपए की रकम रखी गई है। इस बात की भी आशा है कि जल प्रबंध और भूमि संरक्षण उपायों के संबंध मे 5,000 अतिरिक्त ट्यूबवैलों तथा पम्पिंग सैटों के वास्ते कृषि पुनः वित्त निगम (एगरीकलचरल फाइनैंस कार्पोरेशन) से धन प्राप्त करने के लिए चल रही बातचीत सिरे चढ़ जाएगी तथा इससे कार्यक्रम का और विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही डीजल की कमी के कारण ट्यूबवैलों को बिजली देने के काम में देरी होने पर भी सिंचाई के लिए जल का प्रबंध हो सके।

हरियाणा राज्य को बाढ़ों से जीवन, सम्पति और अनाज की पैदावार को होने वाली हानि का पूरा ध्यान है। अंतराष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डिवैलपमैंट एसोशियेशन) की सहायता से तीसरी पंच–वर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू की गई बाढ़ों की रोकथाम तथा जल निकास योजना के प्रथम चरण का काम पूरा कर लिया गया है। घग्गर तथा पश्चिमी यमुना नहर के भू–भागों के संबंध मे योजना की दूसरी अवस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के एिल भारत सरकार द्वारा उस संघ के साथ कए

और करार के एिल बातचीत किए जाने की आशा है। इसके साथ ही विचार यह है कि विश्व बैंक के सुझाव पर सिंचाई, खेतीवाड़ी तथा जल विज्ञान के भारतीय तथा विदेशी माहिरों की अध्ययन टीम बनाई जाए, जोकि इन भागों के लिए संगठित तथा विस्तुत योजना भी बनाए और भूमि के नीचे के जल भंडारों की खोज और उनके उपयोग, सेंम की रोकथाम, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की संभावना, खारेपन कोा कम करने, फसल के उचित तरीके चुनने और भूमि तथा जल–प्रबंध की प्रचलित विधियों के संबंध में सिफारिशें भी करें। इस कमेटी की रिपोर्ट तीन वर्ष के अन्दर अन्दर प्राप्त हो जाएगी और विश्व बैंक उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देगा।

खेती की पैदावार बढ़ाने वाले रासायनिक खादों, बीजों, खेती की मशीनों और कीड़ेमार दवाइयों आदि के साधनों को मुहैरूया करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से 67 लाख रूपए के दरमियानी मियाद के कर्जे तथा 409 लाख रूपए के थोड़ी मियाद के कर्जे का प्रबन्ध किया है। इसके इलावा सहकारी भूमि गिरवी बैंक द्वारा देश की प्रसिद्ध वित्तीय संस्थाओं की सहायता से 100 लाख रूपए के ऋण–पत्र जारी करने का भी विचार है। वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस बैंक दे स्टेट बैंक आफ पटियाला से 20 लाख रूपए तक का नकद कर्जा ले सकने की मंजूरी प्राप्त की है। आशा है कि इन

सभी उपायों से राज्य में खेती संबंधी कर्जों के विस्तार के एिल एक सुदृढ़ आधार बनाने सहायता मिलेगी।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिला करनाल में 1 अप्रैल, 1967 में शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खेतीबाड़ी के बढ़िया तरीकों को अपनाने के लिए न केवल विस्तार सुविधाएं दी जाएंगी बल्कि इसके इलावा रासायनिक खाद, बीजों तथा कीड़ेदार दवाइयों के रूप में खेती के प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं की जरूरी मात्रा प्रदान करने के लिए भी भारत सरकार गारंटी देगी। इसके इलावा 1967–68 के दौरान गुड़गांव, रोहतक तथा जींद के तीन जिले, जिला हिसार के छः खंड ब्लॉक तथा जिला अम्बाला के चार खंड अधिक पैदावार दने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार हरियाणा के 82 खंडो मे से 15 खंड सघन–कृषि जिला कार्यक्रम में तथा 44 खंड अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगें।

छोटे किसानों को ट्रैक्टर द्वारा खेती की सुविधाएं देने के लिए एक योजना बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत किसान उचित खर्च के साथ ट्रैक्टर किराए पर ले सकते ळं। इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त एजैंसी की व्यवस्था की जाएगी जिसके पास काफी ट्रैक्टर होगें तथा केन्द्रीय स्थानो पर मरम्मत और सेवा की सुविधाएं भी होंगी। बएिया किस्म के बीज पैदा करने तथा उसकी किसानों को सप्लाई से सम्बन्ध में भारत सरकार ने हिसार में 18000 एकड़ के रकबे में एक बीज तथा भेड़ फार्म खोलने का

प्रस्ताव रखा है। इस फार्म को चलाने के लिए साज–सामान रूस द्वारा दिया जाएगा तथा जब यह फार्म काम करना शुरू कर देगा तो इससे सारे राज्य की बीज की आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी।

पशुपालन के क्षेत्र में, अपने दुधारू तथा बोझा ढ़ोने वाले पशुओं की बढ़ियानस्ल के कारण हरियाणा का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चौथी योजना में पशुओं के सुधार और इलाज की आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए 16.7 लाख रूपये की रकम रखी गई है। गोसवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर जमीन प्राप्त की जाएगी। दिल्ली के आस–पास के इलाके में सघन पशु–विकास–कार्यक्रम आरम्भ किए जाने का विचार है। इसके अन्तर्गत पशु पालने वालों को और अधिक पशु खरीदने के लिए आवश्यक साधन जुटाए जाएंगे। दिल्ली के लोगों की दूध की जरूरतों को पूरा करने के एिल सहकारी डेरियां खोली जाएगी और सरकारी क्षेत्र में क्रीम निकालने का एक कारखाना खोला जाएगा ताकि दूध की बिक्री के लिए काफी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। राज्य के अन्दर गैर सरकारी क्षेत्र में प्रसिद्ध फर्मों को दूध के पदार्थ तैयार करनेके सम्बन्ध में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुर्गी पालन और सुअर पालन के विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे दिल्ली की मण्ड़ी की निकटता का गांवों की अर्थ–व्यवस्था को लाभ हो सके।

राज्य के अधिकांश क्षेत्र में बंजर मरूस्थल या अर्ध मरूस्थल भूमि है। भूमि की क्षमताओं का पूरी तरह से लाभ नहीं

उठाया गया है क्योंकि वर्षा अनियमित रूप सेहोती है और सिंचाई की सुविधाएं काफी नहीं है। बोए हुए रकबे के आंकड़ो में प्रतिवर्ष तथा प्रति भूभाग में वर्षा की मात्रा के अनुसार अन्तर पड़ जाता है। अनाज की वर्तमान कमी के कारण हमें और अधिक क्षेत्र में फसल उगाने और दो फसलों वाले क्षैत्र को बढ़ाने की जयरत है ताकि हमारा राज्य बचत वाला राज्य बन सके। इसलिए विकास योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी और दरमियानी सिंचाई प्रायोजनाओं को पहल दी गई है और उनके लिए 14 करोड़ रूपए की रकम रखी गई है। इस सम्बन्ध में घग्गर बांध प्रायोजनाओं के निर्माण को बड़ा महत्व दिया गया है और चौथी पंच–वर्षीय में इसे एक अधिक पहल वाली प्रायोजना के रूप में शुरू करने का विचार है। यमुना पर किशाऊ बांध भी हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना बहुमूखी होगी तथा इससे सिंचाई और बिजली के संबन्ध में एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार इस योजना के बारे में विस्तृत जांच कर रही है तथा इस कार्य को शीघ्र शुरू करवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इसके इलावा गुड़गांव नहर प्रायोजना द्वारा गुड़गांव जिला में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2.85 करोड़ रूपये तथा पश्चिमी यमुना नहर की शाखाओं को फिर से नया रूप देने के लिए 4.15 करोड़ रूपये रखे गए हैं। इससे करनाल, जींद, रोहतक, हिसार तथा महेन्द्रगढ़ जिलों को काफी लाभ पहुंचेगा। पश्चिमी यमुना नहर फीडर प्रायोजना से राज्य में और अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। जलाशय तथा उठान सिंचाई समेत छोटी सिंचाई योजनाओं से

चौथी योजना के दौरान गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ जिलों मे 8 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी। बाढ़ तथा सेम के दोहरे खतरे की भी रोक थाम की जा रही है तथा चौथी योजना मे इस बारे मे 5 करोड़ रूपए अलग रखे गए है।

14. आर्थिक विकास उद्योगो की समृद्वि पर निर्भर है। कारखानो में मशीनों की यूज अर्थव्यवस्था की सजीवता की ठीक वैसे ही द्योतक है जैसे कि राज्य के कच्चे माल तथा खनिज पदार्थ के साधनो का पूर्ण रूप से लाभ उठाया जाए तथा उघोगों में आधिक से अधिक धन लगाया जाए। यह संतोषजनक है कि प्रारम्भिक अड़चनों और मुश्किलों के बावजूद, सरकार ने हरियाणा को औधोगिक दृष्टि से जल्दी उन्नत बनाने के प्रयत्न शुरू कर दिए है। जल्दी ही एक उघोग विकास निगम 7 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूजिं से कायम किया जाएगा प्रशंसा जिससे औघोगिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके, वर्तमान औघौगिक प्रायोजनाओं को सुधारा जा सके और नई प्रायोजनाओ शुरू किया जा सके। हिसार में डली लोहे पिग आयरन के कारखानो की प्रगति को और तेज किया जा रहा है। छोटे पैमाने के उद्योगो को तथा निर्यात की सुविधाओं को बढावा देने के लिए एक अलग नियम बनाया जाएगा। हरियाणा वित नियम भी अगले वित वर्ष मे कायम हो जाएगा जिसमे राज्य के ओघोगिक कार्यक्रम मे महत्वपूर्ण योगदान की आशा की जाती है। उघोगो का तोता बाधंने तथा उसे सुढृड़ बनाने के लिए संभावी केन्द्रों (कोकल प्वाइंटों) के विकास की

ओंर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां भावी उद्यमकर्ताओं (एंटरीप्रिन्योर) को विशेष प्रेणाएं एवं सुविधाएं देकर ऐसे केन्द्रों की स्थिति के प्राकृतिक लाभ प्राप्त किए जा सके। छोटे स्तर के उधोग क्षेत्र का विकास किया जाएगा ताकि वह बड़े स्तर की प्रायोंजनाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सके। इसीलिए सहकारी समितियो के जरिए गांवो में उद्योग कायम करने पर बल दिया जा रहा हैं। सामान्य सेवा–सुविधा–केन्द्रों के जरिए लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए जाने वाले माल को प्रामाणिक रू देने के लिए सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी योजनाओं का लागू करना बहुत हद तक बिजनी मिलने पर निर्भर है। जैसे कि सबको ज्ञात है, भाखड़ा नंगल प्रायोजना का नियंत्रण तथा प्रबन्ध, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को सौपा जाना है। इसी तरह ब्यास प्रायोजना के निर्माण का काम भी केन्द्रीय सरकार को ब्यास निर्माण बोर्ड द्वारा करवाना है। यह बोर्ड भाखडा के दाहिने किनारे के बिजली घर के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होगा। भाखड़ा नंगल प्रायोजना के अन्तर्गत 220 कि० वा० मुख्य लाइनों और उप–केन्द्रो (सब–स्टेशनो) के निर्माण–कार्य की जिम्मेदारी भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड की रहेगी। राज्य मे अन्य स्थानों पर बिजली पहुचाने का काम हरियाणा बिजली बोर्ड द्वारा शुरू किया जाएगा, जिससे जल्दी ही बनाया जा रहा है। अगले साल बिजली की सप्लाई बढ़ जाएगी

क्योकि हरियाणा को भाखड़ा के दाहिने किनारे के बिजली घर द्वारा पैदा की जाने वाली श्रतिरिक्त 600 मैगावाट बिजली मे ंसे अपना हिस्सा मिल जाएगा। पन्द्रह मैगावाट की क्षमता वाला एक थर्मल प्लाटं फरीदाबाद के स्थान पर हाल ही में चालू किया गया है और उसी स्थाल पर 55 मैगावाट बिजली की क्षमता वाला एक और थर्मल प्लाटं लगाने के लिए भारत सरकार से धन नियत करा लिया गया है। इसके बावजूद अनुमान है कि चौथी पंच–वर्षीय योंजना के अन्त मे बिजली की सप्लाई मे 178 मैगावाट तक की कमी रहेगी। इसलिए दो नई स्कीमो आर्थात् पश्चिमी यमुना नहर प्रायोजना तथा यमुनानगर थर्मल बिजली प्लाटं को पूरा करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। इसके चालू होने से बिजली की कमी बहुत हद तक दूर हो जायेगी।

कहा तक खेती बाढ़ी के लिये बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध है 1966 में अप्रैल से दिसम्बर के बीच 3,833 ट्यूब–वैलो को कनेक्शन दिए गए। चालू वर्ष के अन्त तक इन की संख्या 5,000 से अधिक हो जाएगी। इसके फलस्वरूप राज्य मे ट्यूबवेल कनैक्शनों की कुल संख्या लगभग 20,000 हो जाएगी। दिसम्बर, 1966 के अन्त तक 1,275 गावों मे बिजली पहुचाई गई थी। अगले वित–वर्षो मे भी नए ट्यूब–वेल कनैक्शन देने का अधिक से अधिक लक्षय रखा जाएगा। इसके साथ ही गावों में बिजली पहुचानें के काम की गति को तेज कर दिया जाएगा।

सडके आर्थिक ढ़ाचे की मूल–आधार होती है। पंचवर्षीय योजना के अन्त में हरियाणा में 446 मील लम्बी राषट्रीय पक्की सड़के और 3,339 मील लम्बी राजकीय पक्की सड़के थी। मौजूदा मुख्य सड़को को बनाए रखने और सुधारने के इलावा नई सड़के खास कर डेरावस्सी, नारायणगढ़ जगाधरी सड़क और श्रम्बाला–जगाधरी सीधी सड़क बनाने और नदी नालों पर पुल बांधने का काम तेजी स`चल रहा है। चौथी योजना के दौरान विचार है कि इन सड़को में अम्बाला–नारायणगढ़ सड़क को बारह महीने प्रयोग मे लाए पा सकने के योग्य बनाया जाए। चौथी योजना के अन्त तक राज्य मे 600 मील अतिरिक्त सड़के बनाने के लिए 8 करोड़ रूप्ये की रकम नियत की गई हैं। चौथी योजना के लिए राष्ट्रीय मुख्य मार्गो के वास्ते एक विकास योजना तैयार करके भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है, जिस पर 11.5 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

परिवहन विभाग, आर्थिक गतिविधियों और नगरों की बढ़ती हुई संख्या के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हरियाणा सरकार के पास शुरू में 475 गांड़ियां थी जो प्रति दिन 64,000 मील चलती थी और उन में लगभग एक लाख यात्री सफर करते थे। पिछले चार महीनों के दौरान 44 नई मर्सीडीज बसे अम्बाला रोडवेज को, 17 नई लेलैंड बसें गुडगाव रोडवेज को ओर 5 लेलैड बसें चण्डीगढ़ डिपो को मुहैया की गई है। आशा है कि अगले वित

वर्ष मे गुडगांव और अम्बाला डिपुओं को 44 पुरानी बसों के बदले इतनी ही नई बसें दे दी जाएगी।

लोगों की बडी देर की मांग को पूरा करने के लिए जगाधरी और दिल्ली तथा दिल्ली और पिलानी के बीच डी–लैक्स बसें दी गई है। चण्डीगढ़ भिवानी मुलाना के रास्ते अम्बाला यमुना नगर और मुलाना जगाधरी के रास्ते अम्बाला कालेसर सीधी बसें चला दी गई है।

करनाल और नीलोखेड़ी, अम्बाला और शाहबाद तथा चण्डीगढ़ और पिजौर के बीच थोड़ी दूरी के यातायात की मागं को पूरा करने के लिए छोटी बसें चलाई गई हैं। करनाल मे हाल ही मे एक माडल बस अड्डा खोला गया है जहां आतिथ्य (हास्पिटैलिटी) विभाग द्वारा चलाए जा रहे रेश्तरों मे यात्रियों को जलपान और खाने पीने का बढिया सामान मिल सकता है। पानीपत, रिवाडी और अम्बाला शहर मे बस अड्डे बनाने के लिए 3 लाख रूपये की रकम रखी गई है। हरियाणा राज्य परिवहन के गुडगांव डिपो को दो हिस्सो मे बांटकर रोहतक में एक नया डिपो बनाया जा रहा है। ताकि बस सेवा और प्रंबध सुचारू ढंग से चल सके।

नागरिक उड्डयन विभाग जन साधारण मे उड़ान जागरूकता को बढ़ावा देने और विभाग चालकों (पायलॅटो) को प्रशिक्षण देने का सराहनीय काम कर रहा है। इस समय हिसार

और करनाल मे एक एक हवाई अड्डा है। हिसार के उड्डयन कलब मे व्यापारिक पायलेट लाइसेंस–धारियों की काफी बड़ी संख्या को प्रशिक्षण दिया है और वह व्यपारिक पायलेट तैयार करने की दिशा मे, जिनकी संख्या अभी तक बहुत ही कम थी, सराहनीय योग दे रहा है। आशा की जाती है कि हिसार और करनाल के उड्डयन क्लब 1967–68 के दौरान 6,000 घंटे उडान कर सकेंगें और लगभग इतनी ही गूलाइडर उड़ाने हो सकेंगी। 40 पायलेटो को सिखलाई देने के लिए हिसार मे अन्य भवनों समेत एक होस्टल बनाया जायगा । अगले वित वर्ष मे दो और पूष्पक विमान तथा ग्लाइडर प्राप्त किए जाएंगे।

20 चालू वर्ष के दोरान कुरूक्षेत्र ओर पिंजौर के दोनों स्थानों पर सेलानी–सूचना केन्द्र खोले गए और भारतीय पर्यटन (Tourism) विकास निगम के सहयोग से दिल्ली से पिंजौर के मुगल बाग तक सर्व–सुविधा–सम्पन्न एक सैलानी (Tourist) बस चलाने के प्रबन्ध किए गए। बड़खल झील, सूरज कुंड, सोहना, कुरूक्षेत्र, पिंजौर और ताजेवाला में पर्यटको (Tourists) को सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1967–68 मे 5.78 लाख रूपये की रकम रखी गई है। दिल्ली के आसपास के अवकाष–क्षेत्र (हालीडे बैल्ट) मे स्थित बड़खल झील और सूरज कुंड के संबंध में विकास योजनाएं अगले वित वर्ष में पूरी कर ली जायेंगी। पर्यटकों के दार्षनीय स्थानों पर सैलानी सप्ताहों (Touris Week) का आयोजन करके सरकार वर्ष 1967 के दोरान अन्तराष्ट्रीय सैलानी वर्ष भी भली

भांति मनाएगी। यह बात उल्लेखनीय है कि कुरूक्षेत्र के इलाके के विकास की और सरकार विषेष ध्यान दे रही है। इसी प्रयोजन से श्री गुलजारी लाल नन्दा की अध्यक्षता और मुख्य मन्त्री की उपाध्यक्षता में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इस बोर्ड को यह काम जल्दी शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

21 संविधान के निदेषात्मक सिद्धातों के अनुसार सरकार अधिक से अधिक लोगों को बढ़िया षिक्षा देने को बहुत महत्व देती है। सार्वजनिक षिक्षा के प्रसार को सुनिष्चित करने के लिए वर्ष 1967–68 में 6 से 17 वर्ष की आयु वाले बच्चो की अतिरिक्त भरती के ये निषाने नियत किए गए है :–

आयु–वर्ग 6 से 11–72,000, आयुवर्ग 11 से 14–18,000 और आयुवर्ग 14 से 17–10,000। अगले वित वर्ष के दौरान 60 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 57 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडल स्कूल और 35 मिडल स्कुलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें हायर सैकंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। इस के साथ ही प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या की और भी ध्यान दिया जा रहा है

षिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये विज्ञान की पढ़ाई की और अधिक जोर दिया जाएगा। अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम चालू किए जाएंगे और अध्यापकों के लिए प्रषिक्षण पाठ्यक्रमों को नई दिषा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक जिले में दो दो उतम स्कूलों

की स्थापना करने का विचार है। षिक्षा देने के संबंध में ये स्कूल अन्य स्कूलों के लिए माडल होंगे। हरियाणा में लडकियों की षिक्षा की और विषेष ध्यान देने की जरूरत है इस दिषा में दो काम किये जाएंगे। एक तो कई मुख्य स्थानो पर महिला विद्यार्थियों के लिए होस्टल बनाएं जाएगें और दूसरे कुछेक चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला अध्यापकों के रहने के लिए भी होस्टल तैयार किए जाएंगें।

जहां तक कालेज की षिक्षा का सम्बंध है, विज्ञान तथा वाणिज्य के लिए एक नया सरकारी कालेज खोलने और एक कालेज में सायंकालीन कक्षाएं आरम्भ करने का विचार है। वर्तमान कालेजों में गणित और अर्थषास्त्र की पोस्ट–ग्रेजुएट कलासें आरम्भ करने के अतिरिक्त दो राजकीय कालेजों में प्रषिक्षण–कक्ष भीं शूरू किए जांएगे। स्कूलों के लिए अपेक्षित व्यायाम षिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए प्रषिक्षण लेने वालों की संख्या बढ़ाने की और भी कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार बढ़ी उत्सुक है कि कुरूक्षेत्र विष्वविद्यालय को प्रत्येक मद्द के अधीन उपयुक्त सहायता मिले और यह विष्वद्यालय शीघ्र ही अधिक से अधिक विकास करें। चौथी योजना के दोराल इस विष्वविद्यालय को अनुदान देने के लिये एक करोड़ रूपया रखा गया है। इसे सम्बन्धक (एफिलियेटिंग) विष्वविद्यालय बनाने का भी विचार है।

इस समय एक योजना पर विचार किया जा रहा है कि गावं और नगरों में कुछ चुने हुए हायर सैकंडरी स्कूलों के साथ लगभग ५० एकड़ भूमि लगा दी जाए जहां बच्चों को खेती बाड़ी के आधुनिक तरीकों का प्रषिक्षण दिया जा सके। इस भूमि पर बीज फार्म तथा सब्जियों के बाग लगाए जाएगें। इस योजना से सम्बन्धित स्कूलों की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही इस योजना से खेतीबाड़ी की पैदावार में भी वृद्धि होगी।

सरकार को स्कूलों तथा कालेज के अध्यापकों के साथ बड़ी सहानुभूति है। सरकार उनके वेतन बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए पहले ही षिक्षा आयोग और भारत सरकार की सिफारिषें सिद्धांत रू॰ में स्वीकार कर चुकी है।

27. सरकार राज्य में जल सप्लाई के सुधार की आवष्यकता के प्रति भी सजग है। इस समय पीने योग्य जल की सप्लाई योजनाएं 32 शहरी खण्ड़ो में विद्यमान है, तथा 17 शहरी खण्डों में मल–निकास के लिए योजनाबद्ध नालियां है। 248 गांवों में सरकारी खर्च पर पीने योग्य पानी दिया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जल सप्लाई तथा मलव्यवस्था योजनाओं के लिए 4 करोड़ रूप्ए की रकम अलग रख ली गई है। 300 अतिरिक्त गांवों में तथा 10 अतिरिक्त शहरी खण्ड़ों में जल–सप्लाई की व्यवस्था करने और 10 शहरी खण्डों में मल–निकास नालियां बनाने का निषाना है। इन सभी योजलाओं पर कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है।

28. एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों तथा अन्य विकासषील शहरों के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। 1967–68 के दौरान इस कार्यक्रम पर 14.36 लाख रूपए खर्च किए जांएगे। नागरिक सामुदायिक विकास योजना के अधीन रोहतक नगरपालिका में मार्गदर्षी प्रायोजना (पायलेट प्राजैक्ट) शुरू की जाएगी। नगरपालिका के कर्मचारियों तथा स्थानीय नगर निकायों के अन्य व्यक्तियों की भलाई के लिए प्रषिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे, ताकि वे स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं को सुयोग्य ढंग से पूरा कर सकें। औद्योगिक विकास और नगरों की वृद्धि से आग लगने का खतरा बढ़ जाने के कारण 25,000 से अधिक आबादी वाले नगरों में पूरे साज–समान वाले फायर स्टेषन खोलने की योजना तैयार की जा रही है।

29. चौथी योजना में सिंचाई के विस्तार तथा अन्य सहायक कार्यक्रमों के जरिये खेतीवाड़ी की पैदावार बढ़ाने पर विषेष बल दिया जाएगा। इसी के साथ आधुनिक मन्डियों और गोदामों की सुविधाएं जुटाने की भी जरूरत पड़ेगी। इन सम्बन्ध में काफी उपाय किए जा रहे है और अगले वित वर्ष के दौरान नई मण्डियों के विकास तथा अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के लिए 13 लाख रूपये की रकम खर्च करने का विचार है।

30. मकानों की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिए मकानों के निर्माण के प्रति जनसाधारण को प्रोत्साहन देना आवष्यक है। गन्दी बस्तियों में रहने वालों तथा औद्योगिक मजदूरों

के लिए सस्ते किरायों पर अच्छे रिहायषी मकानों की व्यवस्था करनी है। इस प्रयोजन के लिए सरकार मकानों सम्बन्धी विभिन्न योजनाएं बना रही है। इनमें औद्योगिक रिहायषी घर, गन्दी बस्तियों का उठाना, थोड़ी आमदनी और दरमियानी आमदनी वाले लोगों के लिए रिहायष–प्रबन्ध, भूमि प्राप्ति और विकास देहाती मकान और कम आमदनी वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए किराए के मकानों की योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों, सहकारी समितियों (औद्योगिक मजदूरों की तथा अन्य), स्थानीय संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों को कर्जे तथा अनुदान दिए जाते है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 100 लाख रूपए की रकम रखी गई है, जिसमे लगभग 3,000 मकानों के निर्माण का काम शामिल होगा और इससे कुछ हद तक मकानों की समस्या कम हो जाएगी।

31. राज्य में ओद्योगिक और रिहायषी बस्तियों के योजनाबद्ध विकास का काम चलता रहा। मकानों की अनियमित वृद्धि को रोकने के लिए, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्धन अधिनियम, 1963 (Punjab Scheduled Roads and controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963) के अधिन फरीदाबाद, बल्लबगढ़, गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, गनौर और यमुनानगर को नियन्त्रित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। फरीदाबाद और बल्लबगढ़ क्षेत्र की स्वीकृत विकास योजनाएं पहले ही प्रकाषित हो चुकी है और अन्य इलाकों की योजनाओं को जल्दी ही अंतिम रूप

दिया जाने वाला है। फरीदाबाद, गुडगांव और सोनीपत में औद्योगिक तथा रिहायषी बस्तियां बनाई जा रही है। फरीदाबाद तथा गुड़गावं मे लोगों को प्लाटों की ब्रिक्री की जा चुकी है। निकट भविष्य में इन स्थानो पर इसी तरह के और प्लाट लोगों को बेचे जाएंगे।

1967–68 के दोरान, राष्ट्रीय सड़कों के साथ–साथ तथा महत्वपूर्ण नगरों के आसपास अव्यवस्थित नागरिक विकास को बढ़ाने से रोकने का काम अन्य इलाकों में भी चालू किया जाएगा। चौथी पंच–वर्षीय योजना के दौरान रोहतक, जगाधरी, करनाल और भिवानी के आसपास के इलाकों के मास्टर प्लान तैयार करने में केन्द्रीय सहायता के लिए भारत सरकार सहमत हो गई है। इन मास्टर प्लानों की तैयारी के लिए 1967–68 के दौरान कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

32 चालू वर्ष के दौरान लोक सम्पर्क विभाग, जनता में सरकारी नीति और विकास कार्य–क्रमों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी को निभाने में सक्रिय रहा है। इसने पिछले साल दिसम्बर में परिवार नियोजन पखवाड़ा और इस वर्ष फरवरी के दौरान योजना प्रचार सप्ताह मनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। हरियाणा राज्य द्वारा उद्योग, कृषि, सिचाई, स्वास्थ्य और षिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्षाने वाली तथा राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने वाली 'हरियाणा दर्पण' नामक प्रदषनी तैयार की गई है और इसे राज्य के सभी भागों में दिखाया जा रहा है। अगले साल इस कार्यक्रम मे 200 सामुदायिक रेडियो सटों की खरीद और तहसील स्तर पर मरम्मत के तीन उपकेन्द्र और सिरसा में क्षेत्र–प्रचार–यूनिट प्रारम्भ करना शामिल है।

33. आप शीघ ही अगले वित वर्ष के लिए बनाए गए बजट प्रस्तावों पर विचार करेंगे और अन्य वैधानिक कार्रवाई करेगे। मुझे विष्वास है कि आपका परिश्रम सफल होगा। मै आपके विचार–विमर्ष में पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। (प्रषंसा)

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : I Beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its December, 1966 Session, and which have since been assented to by the Governor.

STATEMENT

1. The Haryana Contingency Fund Bill, 1966.

2. The Punjab Professions. Trades. Callings and Employments Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1966.

3. The Punjab Laws (Application) Bill, 1966.

OBITUARY REFRENCES

मुख्य मंत्री (श्री भगवत दयाल शर्मा) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मै सदन की और से स्वर्गीय श्री डाक्टर गोपी चन्द जी भार्गव की स्मृति में श्रद्धांजली पेष करता हूं। श्री डाक्टर साहिब हिन्दुस्तान की चन्द गिनी चुनी हस्तियों में से थे जिन्होंने देष की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। न केवल वे

आजादी की जंग के एक बहादुर सेनानी थे बल्कि उन्होंने हमारे सामने अपने सात्विक जीवन के द्वारा जिन्दगी का एक बहुत ऊंचा म्यार रखा था। डाक्टर साहिब का सारे का सारा जीवन पंजाब की और हरियाणा की गरीब जनता की सेवा में लगा है और वे इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि आखिरी क्षण तक उन्हौंने देष की सेवा और गरीब की सेवा नही छोड़ी। बावजूद खराब सेहत के वे हमारे देष के लिए जो भी रचनात्मक पद्धति है, जो भी हमारे रचनात्मक कार्य है, उनमें पूरा भाग लेते रहे। डाक्टर साहिब का पंजाब की राजनीति के अन्दर बहुत बड़ा हिस्सा है। आप पंजाब के मुख्य मन्त्री रहे और अपनी देख रेख के अन्दर पंजाब की उतरोतर वृद्धि के वे बहुत निष्ठावान थे। उनके ऊपर गांधी जी के असूलों का बहुत बड़ा प्रभाव था। रचनात्मक कार्यो के अन्दर उन्होने खादी की सेवा की। ऐसा पुण्य आदमी हमारे बीच से जब उठता है तो एक ऐसी कमी हो जाती है जिस को पूरा करना बहुत मुष्किल है लेकिन हमारे सामने वह कुछ ऐसे पद–चिन्ह छोड़ जाता है जिन के ऊपर चलने से हम वास्तव मे अपना और देष का कल्याण कर सकते है। मै सदन की और से उनके परिवार को हमदर्दी पेष करता हूं और उनकी पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अभी दो तीन दिन हुए हमारे स्पीकर साहिब के पिता जी का देहांत हुआ है। राओ बहाल सिंह एक बहुत सादा तबीयत के और गरीब आदमी की सेवा करने वाले ऊंचे चरित्र के इन्सान

थे। उन्होंने अपने जीवन के अन्दर एक ही लक्ष्य बनाया था कि ईमानदारी से अपने देहाती जीवन के क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा करनी है और आखिर तक उन्होने इस चीज को निभाया।

उन्होने हरिजनों और दूसरे गरीब बच्चों की षिक्षा के लिए काफी सरांहनीय प्रयास किया। मैं उनके परिवार के लिए हमदर्दी पेष करता हूं और उनकी स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धांजलि पेष करता हूं।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर महोदय, आज हरियाणा विधान सभा डाक्टर गोपी चन्द जी भार्गव के चले जाने पर हार्दिक खेद प्रकट करती है। वे ऐसी विभूति थे जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपने जीवन के सुख ऐष्वर्य को लात मार कर अपनी चढ़ती जवानी को लगाया। मुझे वे दिन याद है जब कि मैं विष्वविद्यालय में पहले वर्ष में पढ़ता था और धोखे से उनको ले जाकर सरकार ने उनके ऊपर हमले करवाए। उनकी फराख दिली, उनकी उदारता की पराकाष्ठा इस बात में थी कि प्रधान मन्त्री के कहने पर भी दंड़नीय कार्य करने वाले को दंड दिया जाएगा उन्होने सारी बात जानते हुए भी केस दर्जें नही कराया। जहां वे आजादी की लड़ाई में आगे थे, वहां पंजाब लैजिस्लेटिव असैम्बली में भी उनका इतिहास रहा और उस पार्टी के वे लीडर रहे और उन्होने, कहना चाहिए, बड़ा भारी कंट्रीब्युषन किया। देष के बट जाने के बाद पंजाब के पहले मुख्य मंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की डांवाडोल स्थिति के कारण बीच में राज्यपाल

शासन आया और वे उस संस्था को छोड़ गए जिसके माध्यम से उन्होंने जनता जनार्दन की सेवा की थी। लेकिन हिन्दी आन्दोलन चलने के बाद पुनः शासन कर्ताओ का ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी मौजूदगी में सूबे की हालत सुधर सकती है, लिहाजा उन्हे सरदार प्रताप सिंह कैरीं के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। उनका जीवन आदर्षमय और अनुकारणीय जीवन था। और भी बहुत से मुख्य मंत्री देखे मैने, परन्तु उन्हें मैं बड़े निकट से जानता हूं और उनके परिवार को भी जानता हूं। उनके सुपुत्र यहां पर मैडिकल अफसर रहे। बड़ा सादा जीवन था उनका। बहुत अच्छा स्वभाव था। डाक्टर मार्ग व प्रषासन के तरीकों को समझने वाले बड़े भद्र पुरूष थे। जहां वे आजादी की लड़ाई में आगे आगे रहे वहां प्रषासन के कार्यों को भी बड़ी कुषलता और निपुणता के साथ उन्होंने निभाया। रचनात्मक कार्यों में भी, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, उनकी रूचि थी।

स्ंसार का नियम है कि जो जीव संसार में आता है उसको जरूर जाना होता है चाहे छोटी उम्र में जाए चाहे बड़ी में जाए लेकिन डा० भार्गव जैसे व्यक्ति का जीवन सफल समझा जाना चाहिए जिन्होंने अपनी सारी उम्र देष–सेवा में गुजार दी। उनके चले जाने से एक बड़ा भारी स्थान रिक्त हुआ है। आजकल के कांग्रेस नेताओं के आदर्षों के विपरीत उनके आदर्ष थे। वास्तव में उनका त्याग और बलिदान का जीवन था और उनके निधन पर

केवल हरियाणा को ही नहीं बल्कि सारे देष और समाज को दु:ख हुआ है।

एक और महान व्यक्ति के निधन पर मैं श्रद्धांजलि पेष करता हूं यानी राओ बहाल सिंह जी हमारे सम्मानवीय अध्यक्ष के पूज्य पिता थे। बड़े आष्चर्य की बात है कि इधर तो उनके पुत्र अध्यक्ष के पद पर विराजमान हो रहे थे। और उधर वे स्वर्ग सिधार रहे थे। जीवन में ऐसी प्रिय और अप्रिय बाते हो जाया करती है। हम जानते है कि उनके परिवार ने देष की स्वतंत्रता मे बड़ा हिस्सा लिया। उनके जीवन क्षति से जनता जनार्दन को दुख होना स्वाभाविक है। फिर भी इस संसार से जाते जाते अपना एक होनहार लाल हमें दे गए जो आज हमारे सामने माननीय स्पीकर के पद पर उपस्थित है। उनके स्वर्गवास हो जाने से हमें बड़ा दुख हूआ है। भगवान उन की आत्मा को शान्ति दे।

श्री भगवान देव प्रभाकर (भिवानी) : आज पंजाब और हरियाणे के ही नही बल्कि समूचे देष की महान विभूति डा० भार्गव के निधन पर समस्त सदन शोक ग्रस्त हो रहा है। शोक सागर में हिलोरे लेते हुए मै जन संघ पार्टी की तरफ से उस महान विभूति को भाव–भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डा० भार्गव प्रजातन्त्र के प्रखर खिलाड़ी थे, महात्मा गांधी के आदर्षो कै पुजारी थे और सादगी के पुतले थे तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। वे जिला हिसार के रहने वाले थे। मै उन्हें भली भांति जानता था। उन्होंने जिला हिसार के सर्वश्रेष्ठ, पावन, पवित्र परिवार में जन्म लेकर

भारत माता के नाम को रोषन किया। उन्होंने लाहौर के अंदर षिक्षा प्राप्त की। उसके पष्चात राजनीतिक क्षेत्र के अन्दर उन्होंने जो देष की सेवा की उसके लिए पंजाब के राजनितिक गगन–मंडल में सूर्य के समान चमकते रहेंगे। वह दो बार पंजाब में मुख्य मन्त्री, वित मन्त्री तथा अन्य प्रषासनिक उच्च कोटि के प्रषासन पदों पर आसीन रहे और प्रषासन के अन्दर उन्होंने बड़ा भारी योगदान दिया। देष के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बड़ा भारी भाग लिया। उन्होंने जो जो काम किए वे बड़े प्रषंसनीय है। अगर यह कहा जाए कि वे गागर में सागर थे तो कोई अतिष्योक्ति नहीं होगी। उन्होंने नाना प्रकार के काम जनता के उत्थान के लिए किए। वे उच्च कोटि के लेखक थे, उच्च कोटि के षिक्षक थे तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके निधन से सिर्फ हरियाणा को ही नहीं बल्कि सारे देष को धक्का लगा है। मै समझता हूं कि आज संसार से उनके उठ जाने से केवल पंजाब और हरियाणे की जनता को ही क्षति नहीं पहुंची बल्कि सारे महान् देष की जनता को पहुंची है। मै उनको फिर श्रंद्धाजलि अर्पित करता हूं।

ठसके साथ ही मै अपने सदन के स्पीकर महोदय के पिता राओ बहाल सिंह जी को श्रंद्धाजलि अर्पित करता हूं जिनके जीवन का अधिकांष भाग जनता की सेवा में और भारत माता की सेवा में तथा अन्य श्रेष्ठ वातों में बीता है। उस महान विभूति और उच्च कोटि के पवित्र मानव के निधन पर, जिनके महान पुत्र आज हमारे इस सदन के अध्यक्ष के पद पर आसीन है, दुःख होना तो

अवष्यमभावी है। वे एक उच्च कोटि के देषभक्त थे। इसलिए हम दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : मै अपनी और से तथा सदन की और से डाक्टर गोपी चन्द भार्गव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डाक्टर साहिब ने अपना अधिकतर जीवन देष की आजादी प्राप्त करने के लिए जेलों में बिताया और अनेक कष्ट सहे। अन्त में उनके प्रयत्न सफल हुए और देष आजादी हासिल करने में कामयाब हुआ। उसके पश्चात् वे मुख्य मंत्री बने तथा पंजाब गर्वनमैंट के प्रषासन के कई प्रमुख पदों पर काम करते हुए चलाया। जब वह काफी उम्र के हो गए और चीफ मिनिस्टर या वित मंत्री नहीं रहे, तो भी उन्होंने देष की सेवा करने के लिए अपना समय और श्रम लगाया और वह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे। वह बड़ी ही सादा तबीयत के आदमी थे और काफी योग्य थे। उनकी विषेषता यह थी कि योग्य होते हुए भी बड़े ही नम्र थे और छोटे से छोटे आदमी की भी बात सुनते थे। परमात्मा उनके परिवार को शक्ति दे कि वह इतने बड़े सदमे को बर्दाषत कर सकें, और दिवंगल आत्मा को शन्ति दे।

मैं राओ बहाल सिंह को भी अपनी और से हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। परमात्मा उनके परिवार को शक्ति दे कि वह इस सदमे को बर्दाषत कर सके। वह बड़े कर्मठ व्यक्ति थे और ८० साल के होते हूए भी ब्लाक समिति के चेयरमैन रहे तथा अहीर

ऐजुकेंषन बोर्ड के जनरल सक्रेटरी रहे और बार एसोसियेषन के चेयरमैन रहे। उनकी प्रसिद्धि इस बात से पता चलती है कि उनके अन्तिम संस्कार के वक्त लगभग दस हजार से भी अधिक व्यक्ति थे।

मै हाउस के आनरेबल मैम्बरान से दरखास्त करूंगा कि वह दो मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।

(इस पर दो मिनट के लिए सभा मौन खड़ी रही)

Presentation of the Financial Statement for the period from 1st November, 1966 to 31st March, 1967.

वित मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य बना। उस वक्त से अब तक के लिए जो कुछ खर्च हुआ उस का विवरण में विधान सभा के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत करती हूं।

महोदय. पहली नवम्बर, 1966 को अलग हरियाणा राज्य बन जाने से राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च का प्रधिकार लेना आवष्यक हो गया था। यह प्रधिकार पहली नवम्बर, 1966 की धारा 42 के अधिन, भूतपूर्व पंजाब राज्य के राज्यपाल ने 28 अक्तूबर, 1966 को खर्च का प्राधिकार दे दिया था। इस प्रकार हरियाणा की संचित निधि से कुल 85,67 लाख रूपया (52,98 लाख रूपया पारित और 32,69 लाख रूपया प्रभारित) खर्च करने

की मंजूरी दी गई थी। राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत खर्च की यह रकम हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी सिद्ध हुई, परन्तु कुछ विषेष मामलों में आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यपाल से 292 लाख (259 लाख रूपए पारित और 33 लाख रूपए प्रभारित) का और अधिकार प्राप्त किया गया । राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किए गए आज तक के खर्च की कुल रकम 69,81 लाख रूपये (36,80 लाख रूपये पारित और 33,01 लाख रूपए प्रभारित) बनती है।

विभागों को यह कहा गया था कि वे पहली नवम्बर, 1966 से 31 मार्च, 1967, तक पांच महीने की अवधि के लिए प्राप्तियों के अनुमान तैयार करें। अनुमान है कि इस अवधि के लिए हरियाणा राज्य की कुल प्राप्तियों 60,47 लाख रूपए होंगी। कुछ दूसरे जमा खर्च करने के बाद पाँच महीने की अवधि के लिए प्राप्तियों और खर्च के अनुमान से 762 लाख रूपए का घाटा निकलता है, जो कि इस प्रकार है :–

(i)	राजस्व लेखा–	
	(क) राजस्व प्राप्तियां	2536
	(ख) राजस्व खर्च	2554

	बचत (+) कमी (–)	(–) 18
(ii)	पूंजी लेखा	413
(iii)	सार्वजनिक ऋण–	
	(क) लिए गए ऋण–	32.4
	(ख) लौटाए गए ऋण निवल	2908 + 335
(iv)	कर्जे तथा पेषगियां–	
	पेशगियां	1105
	वसूलियां	267
	निवल	–838
(v)	फुटकर निधि	+75
(vi)	अनिधिक ऋण (निवल)	+22
(vii)	जमा तथा पेषगियां (निवल)	+67

(viii)	प्रेषण (निवल)	+8
	बजट का घाटा (–)	–762

PRESENTATION FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM 1ST NOVEMBER, 1966 TO 31ST MARCH, 1967

राज्य की प्राप्तियां और खर्च के संषोधित अनुमानों का हिसाब लगाया जा रहा है और वर्ष 1967–68 का बजट पेष करते समय इन्हे भी विधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मै यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहवी हूं कि प्राधिकृति खर्च की हद के अन्दर रहते हुए पूरी किफायत बरती गई है और आषा है कि असली घाटा कम हो कर लगभग 3 करोड़ रूपए रह जाएगा।

राजस्व लेखा–

राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में केन्द्रिय सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त 251 लाख रूपये, केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रू॰ में 396 लाख रूपए, राज्य के करों से प्राप्तियों के रू॰ में 881 लाख रूपए, ब्याज से प्राप्तियों के रूप मे 489 लाख रूपए और परिवहन तथा संचार से प्राप्तियों (सड़कों से होने वाली प्राप्तियों को छोड़कर) के रूप में 116 लाख रूपए की रकम शामिल है राजस्व खर्च की महत्वपूर्ण मद्द ये हैं – ऋण

सेवाओं के लिए 383 लाख रूपए, प्रषासकीय सेवाओ के लिए 256 लाख रूपए, सामाजिक तथा विकास संबंधी सेवाओं के लिए 963 लाख रूपए और लोक निर्माण के लिए 105 लाख रूपए।

पुंजी लेखा

पूंजीगत खर्च में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के लिए 82 लाख रूपए फुटकर निधि में डालने के लिए 75 लाख रूपए और लोक निर्माण कार्यों पर खर्च के लिए 101 लाख रूपए की रकम शामिल है।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण की रकम मे आमदनी तथा खर्च की मदों के अन्दर चलते ऋण के रूप मे 2379 लाख रूपए शामिल है। यह अस्थायी ऋण रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिए गए है ताकि सरकार की थोड़ी अवधि की कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके। इन्हें इसी वर्ष लौटाया जाना हैं। इस मद्द को छोड़कर 864 लाख रूपया का सार्वतनिक ऋण लिया गया और 529 लाख रूपए सार्वजनिक ऋण का भुगतान किया गया। सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप में विकास के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार से लिया गया

जबकि लौटाया ऋण गया अधिकतर भारत सरकार से पहले प्राप्त किए गए कर्जो के भुगतान के संबंध मे है।

ऋण तथा पेषगियां

स्थानीय निधियों गैर–सरकारी (प्राईवेट) पार्टियों तथा सरकारी कर्मचारयों आदि को दिए गए कर्जो की वसूनी का अनुमान 267 लाख रूपए बनता है ; स्थानीय निधियों प्राईवेट पार्टियों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों का अनुमान 11,06 लाख रूपए है। इसका अधिक भाग तो बिजली प्रायोजनायों पर किया जाने वाला खर्च है जिसे अन्त में राज्य बिजली बोर्ड को ऋण के रू॰ में अन्तरित कर दिया गया। बाकी रकमें अधिकतर कृषि विकास आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण है।

{वित मन्त्री}

मुझे माननीय सदस्यों को सुचित करना है कि राज्यपाल द्वारा अधिकृत खर्च का अनुमान मोटे तौर पर करना पड़ा क्योंकि वह पुनर्गठन के समय वित वर्ष के बीच लगाना पड़ा और पहले खर्च किए धन का ठीक अनुमान नही लगाया जा सकता था। इन गणनाओं के लिए जिन बातों को आधार माना गया है, उनका व्योरा वित विवरण संबंधी ब्याख्यात्मक टिप्पणी में दिया गया है।

अब मै सदन के सामने हरियाणा राज्य के 1 नवम्बर, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक को आमदनी तथा खर्च का वित–विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूं।

जयहिन्द।

श्री मंगल सैन : आन ए प्वांयट आफ इनफर्मेषन, सर।

डिप्टी स्पीकर साहिब, अखबार में छपता है और रोज रोज छपता है कि चौधरी जयवंतसिंह और श्री दोनमुहम्मद ने ट्रैयरी बैचिज को ज्वायन कर लिया है और इसी तरह श्री धन सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है, मेहरबानी करके आप यह स्पष्ट कर दीजिए कि क्या यह ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष : जब कांग्रेस व्हिप ने लिख कर दिया था कि चौधरी जसवंत सिंह ने और दीन मुहम्मद ने कांग्रेस ज्वायन कर ली है तो ऐसा मालूम होता था, मगर उन्होंने कोई ऐसी सूचना नहीं भेजी कि उन्होंने कांग्रेस ज्वायन की है। और जो श्री धन सिंह का सवाल है उन्होंने पहले लिख कर दिया था लेकिन अब उन्होंने लिख कर दिया है कि मै विदड्रा करता हूं और कांग्रेस ज्वायन नहीं करता इसलिए तीनों ही अभी तक आपोजोषन के अन्दर है।

(The house stands adjourned till 9.30 a.m. on the 22nd March, 1967.

The sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday the 22nd March, 1967.